**13.00 hrs.**

Title: Shri Yogi Adityanath called the attention of the Minister of Environment and Forests regarding situation arising out of pollution being caused in river Ganga due to Industrial effluents and steps taken by the Government to prevent it.

**योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) :**अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विाय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

" गंगा नदी में औद्योगिक अपशिट छोड़े जाने के कारण होने वाले प्रदूाण से उत्पन्न स्थिति और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। "

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): Mr. Speaker, Sir, Ganga Action Plan (GAP) was started in 1985 with the objective of improving the water quality of the river to acceptable standards. Under the first phase of GAP, pollution abatement works were taken up in 25 Class I towns in Uttar Pradesh (UP), Bihar and West Bengal.

To address the problem of pollution of Ganga from industries, a total of 187 grossly polluting industries have been identified for monitoring. Of these, 133 industries have installed effluent treatment plants and the remaining 54 are closed. The State Pollution Control Boards (SPCBs) and the Central Pollution Control Board (CPCB) are regularly monitoring these industries.

In January and February, 2003, the water quality of Ganga at Sangam at Allahabad was affected due to discharge of coloured effluents from distilleries and agro-based industries upstream of Kanpur. After the intervention of the CPCB and the UP Pollution Control Board (UP PCB), the discharge of these effluents was stopped in early March, 2003. The UP PCB has been directed to take action against the defaulting industries and to ensure that such industries do not discharge effluents into the river during non-monsoon months.

* (Placed in Library, See No. LT.7749/2003)

As regards the domestic pollution, total waste water estimated in 1985 was 1,340 million litres per day (mld). Against this, due to resource crunch, works corresponding to a treatment capacity of 873 mld. Only (65%) were taken up under GAP Phase-I which has been declared complete in March, 2000. The total expenditure incurred on the project is Rs. 452 crore. However, since the present estimated waste water generation in towns along Ganga is about 2,500 mld., the sewage treatment capacity created under GAP Phase-I presently correspond to about 35 per cent of the total load only. Part of the remaining pollution load (about 800 mld.) has been taken up under the ongoing GAP Phase-II. The balance of about 830 mld. (most of which is in Hardwar, Allahabad, Varanasi and Patna) could not be taken up due to shortage of funds in the Tenth Five Year Plan.

After the implementation of GAP Phase-I, problems of operation and maintenance (O&M) of assets have been reported. The responsibility of O&M of assets rests with the implementing agencies of the States which have not been able to provide adequate funds for this purpose. With the interaction of the Government at various levels in the States, the situation has now been showing improvement in this regard. The Government of Uttar Pradesh, through a Cabinet decision, has decided to provide adequate and timely funds for O&M to the agencies out of the devolution of funds of the State Finance Commission. The Government of Bihar has also taken a decision to provide matching funds for this purpose. In West Bengal, the situation with regard to the O&M is reported to be satisfactory.

**13.03 hrs.** (Shri P.H. Pandian *in the Chair*)

**योगी आदित्यनाथ :** सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो बातें कही हैं और गंगा प्रदूाण के बारे में जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है, उन में से उन्होंने औद्योगिक प्रदूाण और वे महानगर, जो गंगा के किनारे स्थित हैं, उनके अवशिट जल द्वारा जो प्रदूाण होता है, उसकी ओर ध्यान आकृट किया है, वह भी पूरी तरह संतोाजनक नहीं है । गंगा प्रदूाण के कारणों में एक प्रमुख कारण गंगा के विभिन्न स्तरों पर बनाये गये बांध हैं जिन्होंने गंगा की प्राकृतिक धारा को रोक दिया है।

सभापति महोदय, दूसरा कारण यह है कि गंगा के विभिन्न किनारों पर औद्योगिक इकाइयां हैं, उन इकाइयों का कचरा है जिन पर अब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाये हैं। उन्हें नदी में गिरा देने से प्रदूाण पैदा हुआ है। तीसरा कारण यह है कि विभिन्न महानगरों के गन्दे नालों का दूाित जल, सीवेज का जल है। उस गंदे जल को बगैर फिल्टर किये हुये गंगा में बहाने से यह स्थिति पैदा हुई है।

माननीय मंत्री जी ने गंगा के प्रदूाण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार 187 उद्योगों का यहां जिक्र किया है। जब कि अगर अकेले कानपुर को देखा जाए तो वहां तीन सौ से अधिक चमड़ा उद्योग हैं। इसके अलावा कानपुर में पेपर मिलें हैं। ऋाकिेश से लेकर गंगासागर तक गंगा के प्रवाह में हजारों औद्योगिक इकाईयां हैं, जिनमें आज तक ट्रीटमैन्ट प्लान्ट्स नहीं लगे हैं। केन्द्रीय प्रदूाण नियंत्रण बोर्ड और प्रदेश प्रदूाण नियंत्रण बोर्ड की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, लेकिन कहीं भी प्रदूाण नियंत्रण के

लिए जो बोर्ड गठित हुए हैं और जो उनका कार्य है, उसमें कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। इनका कार्य कहीं दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने मात्र 187 उद्योगों के बारे में बताया है, यह उन्होंने किस और कब के अध्ययन के आधार पर बताया है, अभी वह 1985 के बारे में बता रहे हैं, 1985 से लेकर 2003 तक काफी प्रगति हुई है और आप किस गंगा एक्शन प्लान की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि उसका कार्य कहीं भी इस रूप में नहीं हो पाया है, जो वास्तव में जनता के हित में हो या जिस उद्देश्य को लेकर इसका गठन किया गया है, वह अपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया है। इन सभी औद्योगिक इकाइयों का चयन किस रूप में किया गया है। अकेले कानपुर में ही तीन से अधिक चमड़ा उद्योग हैं, इसके अलावा वहां पेपर मिल्स भी हैं तथा ऋाकिेश से लेकर गंगासागर तक चाहे उत्तरांचल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, यहां पर औद्योगिक इकाईयों का कचरा गंगा में जाता है और इन औद्योगिक इकाईयों में कहीं भी ट्रीटमैन्ट प्लान्ट्स नहीं लगाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्या करने जा रहा है।

माननीय मंत्री जी ने एक दूसरी बात कही है कि विभिन्न महानगरों का अपशिट जल, सीवेज का जल गंगा नदीं में चला जाता है। उसके लिए कहीं फिल्टर या ट्रीटमैन्ट प्लान्ट्स नहीं लगाये गये हैं। आज के दिन गंगा की अविरल धारा, जो प्राकृतिक धारा है, उसे टिहरी में रोक दिया गया है। जब गंगाजल ही उस प्रवाह में नहीं आयेगा तो औद्योगिक इकाईयों का जो कचरा, अपशिट जल और नालों का गंदा पानी होगा, क्या उससे गंगा के अस्तित्व पर संकट नहीं आयेगा। विभिन्न धर्माचार्यों ने गंगा के अस्तित्व पर संकट के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, वह स्वाभाविक रुप से होगा और इस स्थिति पर इस बार के माघ मेले में प्रयाग में धर्माचार्यों ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है। अगले वर्ा कुंभ का पवित्र पर्व हरिद्वार में होने जा रहा है। उस अवसर पर क्या स्थिति पैदा होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब टिहरी बांध बना था तो क्या वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से राय ली गई थी। दूसरी बात कोटेश्वर में और अन्य स्थानों पर खूनी और लक्ष्मण झूला आदि प्रस्ताि वत बांध हैं, क्या उनके लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से राय ली गई है और इसी के साथ मैं जानना चाहता हूं कि â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You cannot make a speech. You can put your questions.

**योगी आदित्यनाथ :** इसके साथ मैं जानना चाहता हूं कि एक बार इसके पूर्व भी गंगा के अविरल प्रवाह को रोकने का प्रयास हुआ था। 1916 में गंगा के अविरल प्र वाह, जो प्राकृतिक प्रवाह है, उसे न रोकने के लिए एक एग्रीमैन्ट हिन्दू समाज के साथ हुआ था। क्या उसकी ओर भी मंत्रालय का ध्यान आकर्ति किया गया है।

SHRI T.R. BAALU: Sir, In fact, I want to tell the house that, within a year's time, I had twice requested the Members who are part and parcel of the Ganga-Yamuna banks to give their views. I had invited more than 130 Members of Parliament for this, wherein my officers had presented the case before the Members.

I was very much interested to interact with the friends so that the local problems can be solved through the Members of Parliament. On both the occasions only a few Members attended those meetings. On the first occasion, four Members attended the meeting and last week, on the second occasion, only 14 Members of Parliament attended the meeting. I had invited Yogi Adityanath too, but he did not attend that meeting.

They are very much interested. I think Yogi Adityanath is not interested. But the fact remains that out of 187 industries, 133 industries have got ETPs (Effluent Treatment Plants). The 54 plants which were not having the ETPs have been closed. The real problem is this. Sir, last time in *Sangam,* there was coloured water flown into the River Ganga. It was because of that psychologically, people were afraid of taking holy dip in the river Ganga. It is not a pollution at all. Even during the holy period, they used to play with the coloured water. It does not mean that they were playing with the polluted water. Were you able to catch the point? Actually, it is not polluted water. But, Sir, to avoid such things, I have instructed my officers to immediately go and stop the discharging of dirty water into the River Ganga. After treatment, water was being discharged. I have asked the officers to stop all those industries which are discharging dirty water. Only during the rainy seasons, water can be discharged. Till such time, they have to hold water in their industries only. It does not mean that the coloured water has got pollutants. Even during my recent visit to Washington, I went and saw a laboratory. I had also interacted with the engineers and scientists in Washington who said that colour in the bislery could be removed. They have also said that they have not yet achieved that level. They do not have any such technology. If there is any such technology, we can make use of it. Till such time, the coloured water will have to be stored inside the industries only. Only during the monsoon season they can discharge into the river. Of course, it would not have any harmful effect. This is the crux of the issue. Now, I do not think there is any clarification required.

**श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) :** माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसके आधार पर ही मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं तो इस गंगा के मामले में बहुत ज्यादा रुचि रखता हूँ और जितनी बैठकें मंत्री जी ने बुलाई हैं, सबमें मैं उपस्थित रहा हूँ।

महोदय, माननीय चन्द्रसेखर जी भी गंगा के किनारे के रहने वाले हैं। गंगा की वर्तमान स्थिति से यह देश पूरी तरह से अवगत है। जो आंकड़े दिये गये हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं और ये आंकड़े मैं इसलिए गलत कह रहा हूँ कि लोक लेखा समिति का सदस्य होने के नाते मैं गंगा कार्य योजना की समीक्षा करने के लिए अभी टिहरी से पटना तक गया था और 1998 में हावड़ा से इलाहाबाद तक शिप द्वारा आया था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 1985 में जब माननीय राजीव गांधी जी ने गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया था बनारस के दशाश्वमेध घाट से, जिस स्थान से यह कार्य आरंभ किया गया था, वहां खुला नाला अनइंटरप्टैड गंगाजी में गिर रहा है, कहीं कोई अवरोध नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के आंकड़ों से ही बताना चाहता हूँ कि हरिद्वार में 160 एम.एल.डी. डिसचार्ज होता है जबकि ट्रीटमैंट केवल 18 का होता है। इसी तरह से कानपुर में गवर्नमेंट रिकार्ड में 360 एम.एल.डी. डिसचार्ज निकलता है। ट्रीटमैंट कैवल 102 का होता है। ये जो ट्रीटमैंट प्लान्ट लगाए गए हैं और जो पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली की हालत यह है कि वहां चार घंटे ही बिजली रहती है। नतीजा यह होता है कि केवल चार घंटे ये चलते हैं। इन्होंने अपने आंकड़ों में दिखा दिया कि पंपिंग हाउस बना दिये, एस.टी.पी. बना दिये और ट्रीटमेंट हो रहा है। जब वहां पावर ही नहीं होती है तो उस स्थिति में कोई ट्रीटमैंट वहां नहीं होता है और प्रदूति पानी सीधा अनइंटरप्टैड गंगा जी में गिरता है। जो जनरेटर लगाए गए हैं, वह भी मैं बता दूँ कि इलाहाबाद में दारागंज के पंपिंग स्टेशन पर जब मैं पहुँचा, तो वहां जो एक साल पहले जनरेटर लगाया गया था, वह ट्रॉली पर खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि यह ट्रॉली पर क्यों खड़ा हुआ है, तो लोगों ने बताया कि रात को ही लाकर खड़ा किया गया है, यह किसी अधिकारी के यहां चलता था। जब मैंने डीजल भरने वाला रजिस्टर मांगा, तो वह भी वहां नहीं था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गंगा कार्य योजना केवल एक छल है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ।

मेरा पहला सवाल यह है कि गंगा कार्य योजना बनाते समय क्या जो धन आबंटित किया गया था 452 करोड़ रुपये, उसके पहले क्या कोई अध्ययन कराया गया था कि इसमें कितने प्रकार का प्रदूाण और कितनी मात्रा में प्रदूाण गिरते हैं?

सभापति महोदय, मेरा मानना यह है कि गंगा में केवल शहरी प्रदूाण नहीं गिरता है, जैसा बताया गया कि 25 एम.एल.टी. प्रदूाण गिरता है, वह अलग है। उसके अलावा कारखानों का प्रदूाण अलग है। दूसरे उसमें जो लाशें प्रवाहित की जाती हैं और गंगा किनारे घाट पर शव दफनाए जाते हैं, वह प्रदूाण है। गंगा के किनारे धोबी घाट बन गए हैं। उन पर धोबी डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं वह प्रदूाण है। पांचवे नंबर का प्रदूाण खेतों में फर्टीलाइजर डालते हैं, वह वार्ा से बहकर गंगा में आता है।

महोदय, दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि पूरी गंगा कार्य योजना में पैसा भारत सरकार का लगा है, प्रदेश सरकारों ने योजना बनाई, जिला परिदों ने उसे लागू किया और नगर निगमों और नगर परिदों को उसका जिम्मा दिया। उनके पास साधन नहीं हैं। इस बात को स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। इसलिए वे इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पा रहे हैं।

महोदय, नदियां सम्पत्ति किस की हैं, सिंचाई विभाग की। क्या केन्द्र सरकार ने सिंचाई विभाग को विश्वास में लिया, जिन कारखानों का प्रदूाण गंगा में आता है, उनको नियंत्रित करने के लिए क्या केन्द्र सरकार ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को इस योजना में शामिल किया। इसी तरह गंगा के किनारे अनेक शहरों में पर्यटन केन्द्र स्थित हैं, क्या केन्द्र सरकार ने पर्यटन विभाग को इसमें शामिल किया ? â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I have given you enough time. Let the Minister reply.

**श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** अध्यक्ष महोदय, जैसी सरकार की आधी-अधूरी योजना है, वैसे ही आप मुझे बीच में टोक कर मेरे सवाल को भी आधा-अधूरा छुड़वा रहे हैं। कम से कम मुझे सवाल तो पूरा पूछ लेने दीजिए।

महोदय, कितनी नदियां गिरती हैं, यह भी बताया जाए, उन नदियों की हालत क्या है, जो यमुना गोमती और सरयू नदियां हैं, उनकी हालत क्या है ? मुझे सवाल तो पूरा करने दीजिए। जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उन्हें तो पूछ लेने दीजिए, तभी तो मंत्री जी उत्तर देंगे। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You cannot make a speech. I have given you enough time. You please sit down. Let the Minister reply now.

**श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** मैं यह पूछना चाहता हूं कि यमुना, गोमती और सरयू की हालात क्या है, उनमें जो नदियां बहकर गिरती हैं, उनका कचरा निकालने के लिए क्या व्यवस्था की है ? â€¦ (व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU: Sir, the hon. Member has already been informed about this last week when he made a representation. He has got enough materials and he can speak. But at the same time ...(*Interruptions*)

**श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** सभापति महोदय, मुझे प्रश्न भी पूछने नहीं दिए जा रहे हैं। जब मेरा सवाल नहीं सुना जाएगा, तो मंत्री जी क्या उत्तर देंगे और ऐसी स्थिति में मैं सदन में बैठकर क्या करूंगा। मुझे इस बात का अफसोस है। मैं मंत्री जी का क्या उत्तर सुनूं। जब मुझे प्रश्न ही नहीं पूछने दिया जा रहा है, तो मैं मंत्री जी का क्या उत्तर सुनूं। अतः मैं सदन से बहिर्गमन कर रहा हूं।â€¦ (व्यवधान)

**13.17 hrs.**

**(Shri Chinmayanand Swami then left the House)**

**MR. CHAIRMAN: There are a number of notices given by the Members. All of them are waiting here. You are consuming all the time. What is this? Please sit down.**

**Mr. Minister, you can continue your reply.**

**योगी आदित्यनाथ :** सभापति महोदय, आप मंत्री जी से प्रश्न ही नहीं पूछने दे रहे हैं। जब मंत्री जी प्रश्न ही नहीं सुनेंगे तो उत्तर क्या देंगे। â€¦ (व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU: Sir, 75 per cent of the pollution load which the river *Ganges* receives from sewage and only 25 per cent from industries. The main work of containing sewage water flowing into the river is pertaining to the State Government and the local Municipalities. In 1985, the late-lamented leader Shri Rajiv Gandhi hastened to have a project to clean the river *Ganges*. At that time, because of paucity of funds, a sum of Rs. 452 crore had been provided and the total pollution load was of the order of 1340 mld. At that time, within the limited scope, they were able to tackle up to 65 per cent of the pollution load. Now, the pollution load is 2,500 mld. When compared to 872 mld, which has already been tackled, now the remaining percentage is 35 per cent only. We have provided funds for 45 per cent. How do you expect that the river *Ganges* will be cleaned for ever? It is not possible. People should understand that the Municipalities, which are on the banks of the river, should contain throwing of polluted water into the river. But, at the Central Government level, within the kitty, whatever amount that is provided, we have created some assets.

But, once again the assets created will have to be maintained properly. The question mark lies there. We have tried many times with the Governments of Bihar and U.P, but I am not finding fault with them. Both the Governments have been advised properly. During the recent visit, the people have been advised. Now, they are taking up. They have come forward to maintain the assets. If they maintain the assets properly, some good result will occur. I think, most probably, now the things are going in a proper way and the quality of water will be improved as quickly as possible. But, unless and otherwise they provide more funds, we cannot expect good quality of water. But, at the same time, whether we have spent whatever the amount we had, properly or not is not the question. We have received 20 per cent IRR. The Internal Rate of Return, which has been certified by a particular institution, is 20 per cent. It goes to show that the particular project has been successfully completed. We have also provided Rs.400

crore towards Ganga Action Plan-II. It is also making a good progress. So, let us not curse the darkness. Let us have a candle to see that the darkness is removed.

---

MR. CHAIRMAN : Now, Dr. V. Saroja to speak.

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Sir, on my behalf, hon. Member, Shri T.M. Selvaganpathi may be allowed to raise the issue.

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Sir, are you taking up 'Zero Hour'?

MR. CHAIRMAN: Yes.